माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मैं वित्त वर्ष 2016–17 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. मैं सदन के समक्ष उल्लेख करना करना चाहता हूँ कि यह बजट, दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का और उनके भरोसे का, ईमानदारी से सदुपयोग करने का एक दस्तावेज है। इस बजट का मूलमंत्र है – अगर नेक नीयत और समझदारी से काम किया जाये तो काम तेजी से और कम लागत में होता है और जनता को भी बड़े पैमाने पर इसका फायदा मिलता है। हमारी सरकार ने पिछले एक साल में कई अवसरों पर इस बात का प्रमाण भी दिया है।

3. वित्तीय प्रस्तावों पर आने से पहले मैं सदन का ध्यान बजट से जुड़ी कुछ भ्रांति और धारणाओं की ओर भी दिलाना चाहता हूं – इनमें से एक का जिक्र माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने अपने बजट भाषण में भी किया था कि, 'हमें बजट को प्लान, नॉन–प्लान जैसे परम्परागत सांचों से निकाल कर देखना चाहिए'। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि प्लान, नान–प्लान खर्च आम आदमी की समझ से परे की बाते हैं। उसके लिए तो सारा बजट ही सरकार का खर्च है। आम आदमी के लिए बजट को इस रूप में समझना आसान होगा कि जो योजनाएं और प्रोजेक्ट सरकार उसके लिए जा रही है उनके शुरू होने पर कितना खर्च होगा और उन्हे आगे चलाने पर कितना खर्च होगा।

4. बजट से जुड़ी एक और पारंपरिक धारणा है : सरकारों की सफलता – असफलता का आकलन वित्त वर्श में खर्चे की राशि से किया जाता है। जबकि देखा यह जाना चाहिए कि जनता के पैसे का सदुपयोग हुआ कि नहीं? ऑप्टीमम यूटीलाईजेशन हुआ या नहीं? जनता की कितनी भागीदारी रही? कितने प्रतिशत जनता को इसका लाभ मिला? सरकार का मकसद सिर्फ जनता का पैसा खर्च करना नहीं बल्कि यह देखना है कि उसके काम से कितने इंसानों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा।

5. एक और बात यहां मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट हमारी सरकार द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा करने का ही प्रयास है। हमारे लिए चुनाव घोषणा पत्र सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का एक गठबंधन है। यह किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है। चुनाव जीतने के बाद चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों को हम 'जुमला' नहीं समझते। बल्कि मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र सरकार के मंत्रियों के पास मोबाइल फोन में मौजूद रहता है, और लगातार हमें हमारे वायदों की याद दिलाता है।

6. माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरकार, चुनाव के समय किए गए अपने वायदों पर तेजी से काम कर रही है। आज दिल्ली के 90 प्रतिशत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घर आने वाले बिजली के बिल आधे हो गये है। 10 लाख परिवारों को पानी मुफ्त में मिल रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि लोग पानी की बचत भी कर रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड का रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। हमने 'भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस' की नीति लागू करते हुए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है। भ्रष्टाचार के किसी कृत्य में मंत्री सहित, कितने भी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में इस सरकार में कोई देर नही लगती। सरकार ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रोकने के लिए व्यवस्था में कई सुधार किए हैं। आन–लाईन सर्टिफिकेट, ई–लाईसिंसग, आन लाईन ई डब्लयू एस एडमिशन आदि सुविधायें पहली बार व्यवहारिक रूप में लोगों को उपलब्ध हुई हैं। ऐतिहासिक 'दिल्ली जन लोकपाल विधेयक' इस सदन से पारित किया जा चुका है और इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी का लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकने की दिल्ली सरकार की कोशिशों में केन्द्र सरकार द्वारा लगातार अड़ंगा डाले जाने के बावजूद व्यवस्था की खामियों और कमजोरियों को दुरुस्त करने, राजस्व में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने, फिजूलखर्ची रोकने और ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में हम सफल रहे हैं। ईमानदारी से काम करने, जनता के पैसे की चोरी और बर्बादी रोकने से जो संसाधन अतिरिक्त मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल

गरीबों को निःशुल्क दवाइयां देने, मुफ्त पानी देने, आधे दाम पर बिजली देने और किसानों को मुआवजा देने जैसे कार्यो में किया जा रहा है।

7. बजट प्रस्तावों का विस्तार से वर्णन करने से पहले, मैं सरकार की साहसिक ऑड–ईवन योजना को सफल बनाने के लिए दिल्ली की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में दिल्ली की जनता के इस प्रयोग की सराहना हो रही है। दुनिया की सबसे मशहूर पत्रिकाओं में से एक फार्चून मैगजीन ने ऑड ईवन योजना की इस शानदार सफलता से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री को दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में शामिल किया है। इस सदन को इस बात पर भी गर्व होगा कि हमारे मुख्यमंत्री इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। ऑड ईवन में दिल्ली की पूरी जनता की भागीदारी का मैं इस सदन की ओर से अभिवादन करता हूं। ऑड ईवन की सफलता प्रमाण है कि जनता की भागीदारी से प्रदूषण और ट्रेफिक जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान भी निकाला जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शपथ लेने के तुरन्त बाद दिये गये पहले ही भाषण में जनता की भागीदारी को लेकर उन्होंने कहा था कि "आज दिल्ली का प्रत्येक नागरिक मुख्यमंत्री बना है"।

8. मान्यवर, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं जनता से जुड़ी हुई हैं। हमारा लक्ष्य है ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ पूरी दिल्ली का, हर तबके का विकास। हम दिल्ली के किसी एक हिस्से या कुछ खास लोगों के लिए दिल्ली को स्मार्ट सिटी नहीं बनाना चाहते। हमारे लिए स्मार्ट सिटी का मतलब है: एक–एक व्यक्ति के लिए, बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण, साफ–सफाई और रोजगार के बेहतर अवसरों वाला शहर। स्मार्ट सिटी सिर्फ वही शहर हो सकता है जहां सरकार के फैसलों में ईमानदारी और लोगों की भागीदारी हो और व्यवस्था हर आदमी को बराबर सम्मान देती हो।

आर्थिक परिदृश्य

9. 31 मार्च 2016 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में, वर्तमान मूल्यों के आधार पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) बढ़ कर 5,58,745 करोड़ रूपये हो जाने की संभावना है, जो 2014–15 में 4,94,460 करोड़ रूपये था। अर्थात जीएसडीपी में 13 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यह अनुमान वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष मानते हुए दिल्ली के जीएसडीपी के अनुमानों की नई श्रृंखला पर आधारित है। स्थिर मूल्यों पर, दिल्ली के जीएसडीपी में 2015–16 में 8.34 प्रतिशत बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर यानी 7.6 प्रतिशत से काफी अधिक है। राष्ट्रीय स्तर के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में दिल्ली का योगदान 2011–12 में 3.93 प्रतिशत था, जो 2015–16 में बढ़ कर 4.02 प्रतिशत हो गया। जबकि देश की कुल जनसंख्या में दिल्ली की हिस्सेदारी मात्र 1.43 प्रतिशत है। दिल्ली के जीएसडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 82.3 प्रतिशत है, जबकि 15.5 प्रतिशत योगदान के साथ माध्यमिक क्षेत्र यानि औद्योगिक व निर्माण आदि का दूसरा स्थान है, और प्राथमिक क्षेत्र यानि कृषि आदि का योगदान 2.2 प्रतिशत है।

10. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 2015–16 में बढ़ कर 2,80,142 रूपये हो जाने की संभावना है, जो 2014–15 में 2,52,011 रूपये थी। अर्थात दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में करीब 11 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है जो एक अच्छा संकेत है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2015–16 में बढ़ कर 93,231 रूपये हो गई जो 2014–15 में 86,879 रूपये थी। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में करीब 3 गुणा अधिक है।

मूल्य स्थिति

11. हमारी सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निरंतर निगरानी रख रही है, बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति सक्रिय कार्रवाई करती है और उचित समय पर बाजार में हस्तक्षेप करती है। जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में 2015 के दौरान मुद्रास्फीति की दर सबसे कम 4.9 प्रतिशत रही, जो चेन्नई में 7.8 प्रतिशत, मुम्बई में 7.4 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर 5.7 प्रतिशत थी।

वित्तीय स्थिति

12. हमने वैश्विक आर्थिक मंदी और घरेलू आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ की है। हमने अपनी आय के संसाधनों में लीकेज पर नियंत्रण किया है। अपना राजस्व बढ़ाया है और अतिरिक्त संसाधन जुटाकर आर्थिक मंदी पर काबू पाया है। हम चालू वर्ष में कर राजस्व में 17 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जो 2014–15 के दौरान मात्र 2.64 प्रतिशत थी। राज्य आबकारी के मामले में हमें 2015–16 में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि 2014–15 में यह 8.60 प्रतिशत थी। इसी प्रकार स्टैम्प पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत इस वर्ष 21 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 4.3 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि थी। हमारा कर–जीएसडीपी अनुपात जो 2014–15 में 5.4 प्रतिशत था, वह 2015–16 में बढ़ कर 5.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। मैं यहां माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार कही जा चुकी बात को एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि सरकारों के पास पैसों की कमी नहीं है। नीयत की कमी थी। नीयत ठीक हो तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। जनता तो हमेशा से टैक्स देती है। इसलिए कर राजस्व में 17 प्रतिशत, एकसाईज में 31 प्रतिशत और स्टैम्प डयूटी में 21 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोतरी ईमानदार सरकार की वजह से ही संभव हो सकी है।

संशोधित अनुमान 2015–16

13. अध्यक्ष जी, बजट में चालू वर्ष का हमारा गैर–योजना व्यय 22,129 करोड़ रूपये निर्धारित और अनुमोदित किया गया था। मैं, हर्ष के साथ सदन को यह सूचित करता हूं कि चालू वित्त वर्ष में उत्तर और पूर्वी नगर निगम को 551 करोड़ रूपये के अनपेक्षित ऋण देने, जो गैर–योजना व्यय के मूल अनुमानों का हिस्सा नहीं थे, के बावजूद हम अपना कुल गैर–योजना व्यय 21,565 करोड़ रूपये के स्तर तक सीमित रखने में सफल रहे हैं। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि सरकार ने जनता के पैसे का किफायत से इस्तेमाल किया। योजना परिव्यय, जो बजट में 19,000 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था, को 2015–16 के संशोधित अनुमानों

में 16,400 करोड़ रूपये के स्तर पर सीमित करने का प्रस्ताव है। 2015–16 में संशोधित योजना परिव्यय 16,400 करोड़ रूपये, 2014–15 के योजना परिव्यय 13,980 करोड़ रूपये की तुलना में 17.3 प्रतिशत अधिक है। चालू वर्ष के लिए हमारा समग्र संशोधित बजट व्यय 37,965 करोड़ रूपये है, जबकि कुल बजट अनुमान 41,129 करोड़ रूपये के थे।

2015–16 के लिए पूरक मांग

14. अध्यक्ष जी, संशोधित अनुमानों के अंतर्गत 1420.45 करोड़ रूपये की पूरक मांग अपेक्षित होगी। अतः मैं, सदन से पूरक मांगों का अनुमोदन करने की अपील करता हूं।

2016–17 के बजट अनुमान

15. अध्यक्ष जी, वर्ष 2016–17 के लिए कुल बजट अनुमान 46,600 करोड़ रूपये के हैं, जिनमें 20,600 करोड़ रूपये योजना परिव्यय और 26,000 करोड़ रूपये गैर–योजना व्यय के रूप में शामिल हैं।

16. 46,600 करोड़ रूपये के प्रस्तावित बजट के लिए 36,525 करोड़ रूपये कर राजस्व से, 996 करोड़ रूपये गैर–कर राजस्व से, 381 करोड़ रूपये पूंजी प्राप्तियों से, 3,174 करोड़ रूपये लघु बचत ऋण से, 1,400 करोड़ रूपये केंद्रीय बिक्रीकर/वैट के बदले क्षतिपूर्ति से, 1,300 करोड़ रूपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं से, 413 करोड़ रूपये सामान्य केंद्रीय सहायता से, 325 करोड़ रूपये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 432 करोड़ रूपये भारत सरकार से अन्य अनुदानों के जरिए और बाकी राशि प्रारंभिक शेष से जुटाई जाएगी।

17. 2016–17 में 46,600 करोड़ रूपये के कुल प्रस्तावित व्यय में स्थानीय निकायों के लिए 6,919 करोड़ रूपये शामिल हैं, जबकि 2015–16 के बजट अनुमान में यह राशि 5,908 करोड़ रूपये और संशोधित अनुमान में 5,999 करोड़ रूपये थी।

प्रमुख कार्यक्रम

जनता की सरकार, ईमानदार व्यवस्था

18. अमरीकी राजस्व मंत्री जैकब ल्यू के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि "The Budget is not just a collection of numbers, but an expression of values and aspirations" मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :–

19. हमारी सरकार ने प्रशासन को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और तकनीकी सुधार किए हैं। पारदर्शी और समय पर सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट्स परियोजना लागू की गयी है ताकि आम आदमी को परेशानी न हो। इसके तहत नागरिक विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं का, जैसे कि तरह–तरह के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन, घर बैठे ऑन लाईन सर्टिफिकेट प्राप्त करने तक की सुविधा, लाईसेंस लेना, इवेन्ट आयोजन करने के लिए सिंगल विंडो परमिशन लेना आदि लागू कर दी गई हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और दस्तावेजों की जालसाजी रोकने में मदद मिली है। इसे आसान बनाने के लिए 200 प्रकार के शपथ–पत्र जमा कराने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। सरकार ने दिसंबर, 2015 से सरकारी कार्यालयों में जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों के अटेस्टेशन की आवश्यकता समाप्त करते हुए, सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।

20. किसी भी स्मार्ट सरकार के लिए वाई–फाई नेटवर्क एक महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा है। सरकार सार्वजनिक स्थलों पर वाई–फाई उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मॉडल्स पर काम कर रही है। सरकार ने अब तक बसों में वाई–फाई, बुराड़ी में

आउटडोर वाई–फाई और एनडीएमसी में वाई–फाई मॉडल के पायलट प्रोजक्ट शुरू किए हैं। इन मॉडलों से प्राप्त अनुभवों और जानकारी के आधार पर सरकार दिल्ली के आम नागरिकों को उत्तम कोटि का ऐसा वाई–फाई ढांचा उपलब्ध कराएगी, जिसमें सरकारी खजाने पर लागत भी कम से कम आए।

21. शासन प्रक्रिया में स्वराज लाने के लिए सरकार ने बजट तैयार करने में नागरिकों की भागीदारी बढाने के उद्देश्य से स्वराज निधि योजना पिछले वर्ष शुरू की थी। 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इसे प्रायोगिक आधार पर सफलतापूर्वक चलाया गया। मोहल्ला सभाओं के जरिए स्थानीय स्तर पर कार्यों की अनुशंसा की गई और अब उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में इस कार्यक्रम का विस्तार सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। सरकार के स्वराज विजन के अनुरूप प्रत्येक मोहल्ले को स्थानीय स्तर पर कार्यों के क्रियान्वयन के लिए धन दिया जाएगा। मैं, स्वराज निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के लिए 350 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूं।

22. ई–राशनकार्ड सेवाओं के तहत ऑन–लाईन आवेदन करने और ऑन–लाईन ही राशनकार्ड प्राप्त करने की सुविधा का लाभ 5.57 लाख राशनकार्ड धारकों ने उठाया है। दिल्ली छावनी क्षेत्र में प्रयोग के आधार पर राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई है, जिसमें उपभोक्ताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र में पसंद की उचित दर दुकान से राशन प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है। इसे धीरे धीरे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा।

23. 40 उचित दर दुकानों पर प्वाइंट आफ सेल डिवाईस की स्थापना के लिए एक पायलट योजना लागू की जा चुकी है, जिसमें बायोमीट्रिक पहचान के बाद राशन जारी किया जाता है। इस प्रणाली का विस्तार 6 महीने में 2,400 उचित दर दुकानों में किया जाएगा ताकि अनाज का वितरण पारदर्शी ढंग से सही उपभोक्ताओं को सुनिश्चित किया जा सके।

24. विभिन्न समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत सभी भुगतान आधार से जोड़कर वितरित किए जायें इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। जैसे ही संसद से इसकी मंजूरी मिलेगी दिल्ली सरकार इसे सबसे पहले लागू कर देगी।

25. दिल्ली में नागरिकों, विशेषकर निर्धन और उपेक्षित वर्गों, जैसे रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों आदि, जिनके लिए समुचित भोजन प्राप्त करना कठिन है, को पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के लिए आम आदमी कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव है। इन कैंटीनों की कार्य प्रणाली पर निगरानी और समन्वय के लिए ब्यूरो ऑफ अफोर्डेबल मील्स की स्थापना की गई है। आम आदमी कैंटीन के लिए आगामी वित वर्ष में 10 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा

26. अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल में यह स्वतः प्रमाणित हो गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से है। मैंने पिछले वर्ष का बजट पेश करते हुए भी कहा था कि 'जो समाज शिक्षा के पहले पायदान पर ठीक से कदम रखे बिना आगे बढने की कोशिश करता है उसकी समृद्वि ओर खुशहाली अन्ततः खोखली साबित होती है'। सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगने वाले धन को 'खर्च' के रूप में नहीं बल्कि भावी पीढियों की खुशहाली के लिए निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।

27. हमारी सरकार दिल्ली में शिक्षा के कार्य को तीन हिस्सों में बांट कर देखती है। पहला हिस्सा है – शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधायें और इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरा है पर्याप्त संख्या में योग्य एवं उर्जावान शिक्षक उपलब्ध कराना। तीसरा है इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए और इन अध्यापकों के जरिये छात्रों को ऐसा पाठ्यक्रम देना जिससे वो एक्सलेंट प्रोफशनल तो बने हीं, जिम्मेदार नागरिक और

अच्छे इंसान भी बने। बीते एक वर्ष में हमने इन तीनों पहलुओ पर काम किया है लेकिन फिर भी हमारा फोक्स पहले हिस्से पर यानि बेहतरीन सुविधायें और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर रहा है। 21 नये स्कूल भवन बनकर तैयार हो चुके हैं जिनमें दोहरी शिफ्ट में 42 स्कूल चलाये जा सकते हैं। सरकारी स्कूलों में करीब 8 हजार नये क्लास रूम बन रहे हैं। सम्भवतः जुलाई के महीने से हम इन क्लासरूमस का इस्तेमाल करना शुरू कर सकेंगे। 8 हजार नये कमरों का मतलब है 200 नये स्कूलों के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होना। और अगर इन स्कूलों का दोहरी शिफ्ट में इस्तेमाल होगा तो दिल्ली में इस सत्र से 400 स्कूलों के बराबर का इन्फ्रास्ट्रक्चर और जुड़ जायेगा। इस तरह, सरकार के दूसरे ही साल में, दिल्ली में, 442 नये स्कूलों के जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे शिक्षा विभाग के पास जुड रहा है। यह सब इसलिए हो पा रहा है कि पिछले वर्ष हमने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शिक्षा का बजट दोगुना कर दिया था।

28. अगले वित वर्ष में शिक्षा सबंधी बजट प्रस्तावों पर आने से पहले मैं सदन के समक्ष यह भी बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली के हरेक सरकारी स्कूल में आपको अच्छी सफाई की व्यवस्था हो गई है, सारे टायलेट ठीक करा दिये हैं, बेटियों के लिए अलग टायलेट बनवा दिये गये हैं, सभी स्कूलों में पीने के पानी का इंतजाम हो चुका है और सभी क्लासिस में नये ग्रीन बोर्ड लगा दिये हैं। मैंने स्वयं पूरे वर्ष में करीब 100 सरकारी स्कूलों का दौरा किया है। एक साल के अंदर स्कूलो की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

29. अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के जिम्मे सिर्फ पढ़ाने का ही काम रहे इसके लिए पहली बार निर्णय लिया गया है कि अध्यापकों को जनगणना फैमिली रजिस्टर आदि कार्यों में नहीं लगाया जायेगा। यह मुश्किल, लेकिन जरूरी कदम था। साथ ही स्कूल बिल्डिंग और सुविधाओं के रख–रखाव के लिए हमने देश में पहली बार स्कूलों में एस्टेट मैंनेजर नियुक्त किये हैं। ये एस्टेट मैंनेजर रोजाना अपने–अपने स्कूल में साफ–सफाई, पानी, टायलेट की स्थिति सहित तमाम सूचनाएं और रोजाना की विडियो क्लीप, स्कूल खुलने के एक से दो घंटे के अंदर अपने–अपने डिप्टी

डायरेक्टर को उपलब्ध करायेंगे। इसके लिए एक मोबाईल एपलिकेशन तैयार की गई है। डिप्टी डायरेक्टर इसी मोबाईल एप के जरिये अपने–अपने जिले के हरेक स्कूल की स्थिति, उसमें यदि कोई कमी है तो उसकी सूचना और उस पर लिए गए एक्शन की सूचना सहित, तमाम जानकारी अगले एक घंटे के अंदर सीधे शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री को उपलब्ध करायेंगे। इस तरह स्कूल खुलने के 3 से 4 घंटे के अंदर हरेक स्कूल की जानकारी शिक्षा मंत्री के मोबाईल एप पर उपलब्ध होगी। एक और महत्वपूर्ण योजना के तहत सरकार इस साल हर एक स्कूल के हरेक क्लासरूम में सी सी टी वी कैमरे लगवा रही है। इन सी सी टी वी कैमरों की फीड इंटरनेट के जरिये अधिकारियों, शिक्षा मंत्री और अभिभावकों को उपलब्ध होगी। मैं, इस योजना के लिए वर्ष 2016–17 में, 100 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

30. हमारा मकसद है तीन साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राईवेट स्कूलों से बेहतर स्थिति में लाना। इसके लिए हमने योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रकिया शुरू की है। 5,500 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गेस्ट टीचर्स को स्थाई होने के विशेष अवसर दिये जाने की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए 9,623 अध्यापकों की नई पोस्ट सृजित कर ली गयी हैं।

31. पिछले वर्ष में जहां सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है, अगले वर्ष से हम अध्यापकों और प्रधानाचार्यों की विशेष ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे। हमने अपने अध्यापकों को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेंनिग संस्थानों में भेजने की योजना बनाई है। इनमें हॉवर्ड, कैम्ब्रिज, आक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों के एजुकेशन लीडरशिप ट्रेंनिग प्रोग्राम भी शामिल हैं। SCERT की ट्रेनिंग व्यवस्था और कार्यक्रमों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लिए अगामी वित वर्ष में हमने 102 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है, जो कि वर्ष 2015–16 में मात्र 9.4 करोड़ रूपये था।

32. स्कूलों मे बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम कर उन्हे संगीत, नाटक, कला इत्यादि में भी प्रक्षिशण देने के लिए अलग से पहली बार 8 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

33. खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं इसमें स्कूल के मैदानों को छुट्टी के बाद खेल संगठनों के लिए खोलना, 55 स्कूलों में फुटबाल, टेनिस के अंतर–राष्ट्रीय स्तर के ग्राउण्ड तैयार करना भी शामिल है। सरकार दिल्ली में एक खेल प्रतिभा विकास विद्यालय शुरू करने और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने पर भी काम कर रही है। खिलाडियों को प्रोत्साहन देने और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए इस साल हमने 48 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

34. सरकार ने 205 स्कूलों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए वोकेशनल ट्रेंनिग शुरू की है। हमारा मकसद है कि बच्चे जब स्कूल से निकलें तो एक तरफ उनके अंदर बेहतरीन रिसर्चर, प्रोफेशनल या एकेडिमिकस में आगे की पढ़ाई की योग्यता हो साथ ही उनके हाथ में तुरंत कुछ कर सकने का हुनर भी हो। स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन के लिए हमने 152 करोड़ रूपये का अलग से प्रावधान किया है।

35. पहले ही वर्ष में 205 स्कूलों में, वोकेशनल कोर्स में करीब 45,000 छात्रों ने दाखिला लिया है। वोकेशनल कोर्सस में छात्रों की इतनी दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने पूरी दिल्ली में इस साल 100 से ज्यादा स्मार्ट कैरियर कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया है। ये कॉलेज अलग–अलग क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले निजी कम्पनियां और संस्थानों द्वारा चलाये जायेंगे। स्मार्ट कैरियर कॉलेजों में छात्रों को अलग–अलग क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग दी जायेगी। अगले वित वर्ष में स्मार्ट कैरियर कॉलेज के जरिये कम से कम 50,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दिये जाने का लक्ष्य है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार ने

दिल्ली में युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग देने के लिए स्टेट एप्रेंटिसशिप स्कीम को दुबारा शुरू कर दिया है। यह स्कीम 2006 से बंद थी।

36. सरकार ने नंद नगरी और मंगोल पुरी में दो नयी आई टी आई इस साल प्रारम्भ कर दी हैं। रनहोला, बक्करवाला और जौनापुर में नई आई टी आई और वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर का कार्य तेजी से चल रहा है। आई टी आई कोर्सिस को वाइब्रेंट बनाने के लिए मारूति, सिमंस, माईक्रोसॉफ्ट लेबरनेट और इताशा जैसी कम्पनियों के साथ अनुबंध किये गये हैं। रजोकरी में इसी साल सरकार नया पॉलिटेकनिक शुरू कर रही है। मंडोली, कादीपुर, बक्करवाला और झड़ोदा माजरा में पॉलिटेकनिक का काम तेजी से चल रहा है।

37. स्मार्ट कैरियर कॉलेज, आई टी आई और पॉलिटेकनिक में कोर्सिस करने वाले छात्र ग्रेजुएशन या उससे आगे की पढ़ाई भी कर सके इसके लिए सरकार ने बैचलर ऑफ वोकेशनल (B.Voc) कोर्सिस प्रोग्राम पिछले साल शुरू कर दिये हैं।

38. स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के लिए रोहिणी और धीरपुर में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली (एयूडी) के नए परिसरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी शैक्षिक सत्र से एयूडी का एक नया परिसर कर्मपुरा में शुरू होगा। दीनदयाल उपाध्याय कालेज और शहीद सुखदेव कालेज आफ बिजनेस स्टडीज को आगामी वर्ष के दौरान उनके नए भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव कालेज, भगिनी निवेदिता कालेज और जीजीएसआईपीयू के पूर्वी कैम्पस का निर्माण कार्य 2016–17 में शुरू किया जाएगा। आगे चल कर, विवेक विहार, मंडोली और नरेला में नए परिसरों/कालेजों के निर्माण की योजना है।

39. सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 कालेजों में द्वितीय पाली/ सांध्यकालीन कक्षाओं और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 7 कालेजों में नए पाठ्यक्रमों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

40. मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि लंबे समय से प्रतीक्षित दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस और रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू) ने शैक्षिक सत्र 2015–16 से काम करना शुरू कर दिया है। हमने नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित कर दिया है, जिसे भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। खेल विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है और हमें उम्मीद है कि वर्ष 2016–17 में इन पर काम षुरू हो जाएगा। आईआईआईटी के दूसरे चरण का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है, जिसके पूरा हो जाने पर इस संस्थान में सीटों की संख्या दुगनी हो जाएगी।

41. हमारे विद्यार्थियों के टैक्नोंलोजी और इनोवेषन से जुड़े विचारों को विकसित होने का वातावरण मिल सके, इसके लिए हमने शैक्षिक संस्थानों के लिए इन्क्यूबेशन नीति शुरू की है और 6 विविध संस्थानों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। हमारी आगामी वर्ष में अपने अन्य संस्थानों में भी इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करने और अपने शैक्षिक संस्थानों को उद्यमशीलता, अनुसंधान और इनोवेशन का केंद्र बनाने की योजना है।

42. मैं वित्त वर्ष 2016–17 के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 10,690 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें से 4,645 करोड़ रूपये योजना व्यय के लिए हैं, जो कुल योजना परिव्यय का 23 प्रतिशत है और योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है।

स्वास्थ्य

43. हर साल दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों से 3 करोड़ से अधिक रोगी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में देखे जाते हैं और 6 लाख से अधिक अस्पतालों में भर्ती किए जाते हैं। मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को देखते हुए इतनी बडी आवश्यकता को पूर्ण करना एक कठिन कार्य है और इसके लिए पब्लिक हैल्थ सेक्टर में बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही साथ ही मैनेजमेंट के लिए भी एक ठोस प्रणाली की जरूरत है।

44. दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य सरकार की सबसे बडी प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए पिछले साल स्वास्थ्य का बजट बढ़ा कर ड़ेढ गुणा किया गया था। आगामी वित वर्ष में भी पब्लिक हैल्थ सेक्टर सरकार के विकास कार्यों में केन्द्र पर रहेगा। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार ने 1 मार्च 2016 से दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी दवाईयां और डायगनोस्टिक टैस्ट मुफ्त कर दिये हैं। सरकार दिल्ली के पब्लिक हैल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए तीन स्तरीय प्रणाली की योजना पर काम कर रही है। देश में पब्लिक हैल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए किसी भी राज्य में यह सबसे बड़ा अपग्रेडेशन होगा। अभी तक सरकारों का ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राईवेट सेक्टर पर ही रहा है।

45. सरकार की स्वास्थ्य योजना में सबसे पहले पायदान पर है – मोहल्ला क्लीनिक। स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिक जरूरतें मोहल्ला क्लीनिकों के माध्यम से लोगों की दहलीज पर मुहैया कराने का प्रस्ताव है। मोहल्ला क्लीनिक का डिजाइन आम नागरिकों की सामान्य स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। इन क्लीनिकों में व्यापक डायगनोस्टिक टैस्ट किए जाएंगे और सभी जरूरी दवाइयां दी जाएंगी। मोहल्ला क्लीनिक में कोई विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध नहीं होगा ये केवल सिंगल डॉक्टर ओपीडी क्लीनिक होंगे।

46. दिल्ली का प्रथम मोहल्ला क्लीनिक पिछले कुछ महीनों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है और मात्र कुछ महीनों में ही दुनिया भर में पब्लिक हैल्थ सेक्टर पर काम कर रहे लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की है। वाशिंगटन पोस्ट और शिकागो ट्रिब्यून जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अखबारों ने दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक मॉडल का अध्ययन करने के बाद टिप्पणी की है कि अमेरिका जैसे देशों को भी अपने पब्लिक हैल्थ सिस्टम में सुधार लाने के लिए इससे सबक लेना चाहिए।

47. सरकार ने पूरी दिल्ली में इस वर्ष के अंत तक 1000 मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन साथ ही इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए 100 नये मोहल्ला क्लीनिक तुरंत किराए पर ली गई जगहों पर शुरू किये जा रहे हैं।

48. पब्लिक हैल्थ सेक्टर के थ्री टियर सिस्टम में दूसरे पायदान पर है – पॉली क्लीनिक योजना। पोलिक्लीनिक में मोहल्ला क्लीनिक से एक कदम आगे बढ़कर विशेषज्ञ और टैस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन इनमें अस्पतालों की तरह मरीज को भर्ती करने की सुविधा नहीं होगी। पोलिक्लीनिक की ओपीडी में मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग और बाल चिकित्सा विशेषज्ञ हर रोज उपलब्ध होंगे जबकि अस्थि रोग विशेषज्ञ, नेत्र और ईएनटी विशेषज्ञ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सप्ताह के चुने हुए दिनों में उपलब्ध होंगे। ये पोलिक्लिनिक सरकार के लैब नेटवर्क से जुड़े होंगे और इन क्लिनिकों में व्यापक डायगनोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ईसीजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसे परीक्षणों की सुविधा भी उन क्लीनिकों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सरकार पूरी दिल्ली में 150 पोलिक्लीनिक खोलने की योजना पर काम कर रही है, जिनमें से 20 अब तक चालू किए जा चुके हैं।

49. दिल्ली की पब्लिक हैल्थ केयर सेक्टर का तीसरा स्तर है – अस्पताल। आज खांसी बुखार जैसी सामान्य बिमारियों के लिए भी लोगों को अस्पतालों की लंबी लाईन में खड़ा होना पडता है वहीं अस्पतालों के विशेषज्ञ डाक्टर और विशेषज्ञ सुविधाएं सामान्य बिमारियों के ईलाज में व्यस्त होकर ठप हो जाती हैं। सरकार की योजना

है कि अस्पतालों के बोझ को कम करके मोहल्ला क्लीनिक और पोलिक्लीनिक को इस काम में सक्षम बनाया जाये। इससे अस्पतालों में भीड़ कम होगी और रोगियों के अनुकूल माहौल बनेगा। इस व्यवस्था से डाक्टरों, नर्सों और पैरा–मेडिकल स्टाफ की कार्य–कुशलता में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा।

50. मौजूदा अस्पतालों को री–माडल किया जा रहा है और नए संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। इन सुधारों से राज्य के अस्पतालों में अगले दो वर्षों में अतिरिक्त 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था होगी।

51. सरकार ने व्यापक हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमैंट सिस्टम (एचआईएमएस) की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें एक यूनिक आईडी के साथ नागरिकों को हेल्थ कार्ड प्रदान करना शामिल है। इसमें रोगी से संबंधित जानकारी का रिकार्ड ऑन–लाईन रखा जाएगा।

52. डाइग्नॉस्टिक सर्विसेज, स्वास्थ्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार सार्वजनिक–निजी–भागीदारी (PPP) के अंतर्गत लेबारेटरी और रेडियोलॉजी डाइग्नॉस्टिक सर्विसेज की अपनी क्षमताओं का विस्तार करेगी। इसके तहत स्थापित की जाने वाली लेबारेटरी डाइग्नॉस्टिक सेवाओं के लिए 70 करोड़ रूपये, टेली रेडियोलॉजी के लिए 10 करोड़ रूपये और सीटी/एमआरआई सुविधाओं के लिए 5 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

53. सरकार दवाओं और उपकरण आदि की खरीद और अन्य लॉजिस्टिक्स जुटाने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमैंट में व्यापक सुधार कर रही है और इसके लिए एक स्वास्थ्य निगम की स्थापना की जा रही है। दवाओं और मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के लिए 410 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

54. कैट ऐम्बूलेंसों के वर्तमान बेड़े का विस्तार करने के लिए इसमें 100 सामान्य और 10 अत्याधुनिक ऐम्बूलेंस जोड़ने का प्रस्ताव है। ऐम्बूलेंसों की डिलीवरी जून, 2016 तक हो जाने की संभावना है।

55. राज्य में पॉच "वन स्टॉप सेंटर" काम कर रहे हैं जिनमें दुष्कर्म पीड़िताओं को तत्काल चिकित्सा, पुलिस और परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे दो और केंद्र जल्दी ही राव तुला राम अस्पताल और डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल में काम करने लगेंगे।

56. मैं 2016–17 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5,259 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 3,200 करोड़ रूपये का योजना बजट शामिल है, जो कुल योजना परिव्यय का 16 प्रतिशत है।

सार्वजनिक परिवहन

57. सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़, घण्टों का ट्रेफिक जाम, ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं दिल्ली की बड़ी चिंता है। इनसे बचने के लिए यह जरूरी है कि नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक सुरक्षित, सुगम, एकीकृत और मल्टी मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, सड़कों पर वाहनों की भीड़ में कमी लाने और सार्वजनिक परिवहन के मौजूदा साधनों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे।

58. डी.टी.सी. के बेड़े में 4,461 बसें हैं, जिनमें 3,781 लो–फ्लोर बसें और 680 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें शामिल हैं। सरकार 2016–17 के दौरान 1,000 नई स्टैंडर्ड साइज़ यूबीएस–2 कम्प्लायंट लो–फ्लोर हाइट नॉन–एसी बसें खरीदेगी। वर्तमान में दिल्ली में 1,490 क्लस्टर बसें चल रही हैं और 2016–17 में क्लस्टर योजना के अंतर्गत 1,000 नई बसें जोड़ने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार वित्तीय दृष्टि से समृद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, विशुद्ध रूप से बाजार आधारित मॉडल पर प्रीमियम श्रेणी की 1,000 बसें भी शुरू

करेगी। इन नई बसों को स्थान प्रदान करने के लिए रेवला खानपुर, ढिचाऊं कलां, खरखड़ी नाहर, बवाना सेक्टर–1 और द्वारका सेक्टर–22 में बस डिपो विकसित किए जाएंगे। मैं, बसों की खरीद और बस टर्मिनलों के विकास के लिए 325 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

59. अध्यक्ष जी, 2016–17 के दौरान सराय कालेखां और आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों के जीर्णोद्धार और उन्हें आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है, जिनमें विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। द्वारका में एक नया आईएसबीटी बनाने का भी प्रस्ताव है। पी.पी.पी. मोड में 1,397 नए बस क्यू शेल्टर बनाने का भी प्रस्ताव है।

60. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार दिल्ली में लास्ट माईल कनेक्टिविटी के लिए ई–रिक्शा को बढ़ावा दे रही है। चालू वित्त वर्ष में 3,709 बैटरी चालित वाहनों और ई–रिक्शा मालिकों को सब्सिडी के रूप में 4.97 करोड़ रुपये दिये गए। मैं परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत प्रत्येक ई–रिक्शा के लिए वर्तमान में दी जा रही एकमुश्त 15,000 रूपये की निर्धारित सब्सिडी को बढ़ा कर 30,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

61. प्रयोग के आधार पर एक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। यदि हमें बेहतर परिणाम मिले तो ऐसी और बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर रोड टैक्स के भुगतान से छूट प्रदान करेगी।

62. दिल्ली मेट्रो से करीब 27 लाख यात्री हर रोज सफर करते हैं। यह संख्या दिसंबर, 2016 में मेट्रो परियोजना का तीसरा चरण पूरा होने के बाद बढकर 41 लाख पर पहुंच जाएगी। तीसरे चरण का एक कॉरीडोर – जहांगीरपुरी से बादली नवंबर, 2015 में चालू किया जा चुका है। 2016–17 में 93 मार्गों पर मेट्रो फीडर बसों के बेड़े में 248 नई मिनी बसें शामिल की जाएंगी और उनकी संख्या बढ़ कर 517 हो जाएगी। मैं 2016–17 में डीएमआरसी के लिए 763 करोड़ रूपये प्रस्तावित करता हूं।

63. डीटीसी बसों, मेट्रो रेल और क्लस्टर बसों में यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए कॉमन मोबिलिटी पेमेंट कार्ड के अतिरिक्त सभी बसों में इलेक्ट्रोनिक टिकेटिंग मशीनें लगाई जाएंगी। हम प्रत्येक बस स्टॉप पर एक यात्री सूचना प्रणाली भी लगायेंगे, जोकि बसों की वास्तविक समय स्थिति और उनके पहुंचने के संभावित समय को प्रदर्शित करेगी।

64. मैं परिवहन क्षेत्र के लिए 1,735 करोड़ रूपये का योजना बजट प्रस्तावित करता हूँ, जो 2016–17 में कुल योजना परिव्यय का 8.4 प्रतिशत है।

सड़क ढांचा

65. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए (अरबिंदो मार्ग) तक बारापुला नाले पर ऐलिवेटिड रोड का दूसरा चरण 2016–17 में चालू हो जाएगा। बारापुला नाले पर सराय काले खां से मयूर विहार तक ऐलिवेटिड रोड के तीसरे चरण का निर्माण कार्य 1,261 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है और इसे दिसंबर, 2017 तक पूरा किया जाएगा। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान दोनों परियोजनाओं के लिए मैं 400 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ।

66. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भरोसेमंद बनाने के लिए और मेट्रो की तरह सुगम बनाने के लिए सरकार दो एलीवेटिड बीआरटी कॉरीडोर बनाने की महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रही है, जिनमें एक आनंद विहार टर्मिनल से पीरागढ़ी तक (पूर्वी–पश्चिमी कॉरीडोर–29 किलोमीटर) और दूसरा वजीराबाद से एयरपोर्ट तक ('उत्तर–दक्षिण' कॉरीडोर 24 किलोमीटर) बनाने का प्रस्ताव है। अन्य चार मार्गों पर एलिवेटिड कॉरीडोर, एनएच–24 बाईपास से लोधी रोड तक एक भूमिगत सुरंग और खजूरी खास से भोपुरा बॉर्डर तक कॉरीडोर इम्प्रूवमेंट जैसे कार्य भी 2016–17 में शुरू किए जाएंगे। कॉरीडोर इम्प्रूवमेंट की फिजीबीलिटी स्टडी कराने के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति कर दी गई है और 'विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट' तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है तथा यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए यूटीपैक को भेजा गया है। 'पूर्व–पश्चिम' और 'उत्तर–दक्षिण' एलिवेटिड कॉरीडोरों के सफल कार्यान्यवन के बाद इस मॉडल को पूरी दिल्ली में अपनाया जायेगा।

67. कोलम्बिया में बरगोटा के मेयर एनरीक पेनलोसा के अनुसार "यदि हम परिवहन की बात करें, तो मैं कहूंगा कि महान शहर वह नहीं है, जिसमें राजमार्ग हों, बल्कि वह है, जहां एक बच्चा भी साइकिल या ट्राई साइकिल पर कहीं भी सुरक्षित जा सके"।

68. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सड़कों के डिजाइन संबंधी त्रुटियों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने और उन्हें पैदल यात्रियों/साइकिल सवारों के अनुकूल बनाने के लिए सड़कों के री–डिजाइन और स्ट्रीट–स्कैपिंग की तैयारी कर रही है। सार्वजनिक परिवहन और साइकलिंग को बढ़ावा देने तथा मार्गों को पैदल यात्रियों और विकलांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान प्रायोगिक परियोजना के रूप में 11 सड़कों की री–डिजाइनिंग की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत सड़कों को सुसज्जित करने के लिए ग्लास लिफ्टों, शौचालयों, पौधारोपण, सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइटों और वर्षा जल संरक्षण प्रणालियां कायम करने जैसे उपाय किए जाएंगे। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार 1260 किलोमीटर लंबी सभी पीडब्ल्यूडी सड़कों के लिए किया जाएगा। आउटर रिंग रोड पर विकास पुरी से वजीराबाद (20 किलोमीटर) के दोनों तरफ एक प्रतिबद्ध एनएमवी लेन यानी साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बनाने का भी प्रस्ताव है।

69. मैं, सड़क ढांचा क्षेत्र के लिए वर्ष 2016–17 में 2208 करोड़ रूपये का योजना बजट प्रस्तावित करता हूं, जो कुल योजना परिव्यय का 11 प्रतिशत है।

पर्यावरण

70. सरकार दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण के प्रति अत्यंत चिंतित है। हमने अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों को ध्यान में रख कर प्रदूषण कम करने के अनेक उपाय शुरू किए हैं।

71. हम रियल टाईम बेसिस पर प्रदूषण के स्तर की निरंतर निगरानी कर रहे है। दिल्ली में 6 Ambient air quality monitorining केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनकी संख्या बढ़ा कर 9 करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त एक मोबाइल Ambient air quality monitorining वैन की सेवाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

72. अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। हम शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए जागरूकता पैदा करने के वास्ते हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे मनाते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। हमने जनवरी, 2016 के पहले पखवाड़े में आड–इवेन फार्मूला को प्रयोग के तौर पर लागू किया और अप्रैल महीने में 2016–17 में इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है।

73. अध्यक्ष जी, वायु प्रदूषण बढाने वाले प्रमुख घटकों में सड़कों पर चलने वाले वाहनों से उठने वाली धूल शामिल है। झाड़ू लगाने के दौरान धूल के सूक्ष्म कण उड़ते हैं और उसके बाद हवा में फैले रहते हैं। एक नए कार्यक्रम "सड़कों का व्यापक रख–रखाव" के अंतर्गत अनेक उपाय शुरू करने का प्रस्ताव हैं जिसमें :– सड़कों की मशीन द्वारा सफाई, स्ट्रीट फर्नीचर और संकेतों की नियमित धुलाई और सफाई; मलबे/कचरे को मैकेनाईज स्वीपर के जरिए बायोडिग्रेडेबुल डिस्पोजुबल बैग में एकत्र करना और फुटपाथ और भूमिगत मार्गों की समय–समय पर धुलाई सिविल इलेक्ट्रिकल और बागवानी संबधी कार्य इत्यादि। "सड़कों के व्यापक रख–रखाव"

के इस नए कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 100 करोड़ रूपये का प्रस्ताव करता हूं।

74. कंस्ट्रक्शन एवम डीमोलिशन वेस्ट को री–साइकल करने के लिए हर रोज 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली दो सी एंड डी कचरा परिचालन यूनिटें लिबासपुर और टीकरी बार्डर पर लगाई जाएंगी।

75. अध्यक्ष जी, प्रदूषण के स्तरों, जन–जागरूकता संदेशों और यातायात संबंधी जानकारी आदि को जनहित में प्रदर्शित करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। मैं वर्ष 2016–17 में इस कार्यक्रम के लिए 137 करोड़ रूपये प्रस्तावित करता हूँ।

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण

76. बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि "मैं किसी समाज की प्रगति का पैमाना इस बात को मानता हूं कि उसमें महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।"

77. माननीय अध्यक्ष जी, हमने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक उपाय लागू किए हैं। डी.टी.सी. की 200 बसों में सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। कुछ डीटीसी बसों में प्रयोग के रूप में फ्री वाई–फाई सेवा दिसम्बर 2015 में शुरू की गयी थी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी डी.टी.सी. और कलस्टर बसों में वाईफाई सेवाओं, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने टैक्सियों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए जीपीएस प्रणाली अनिवार्य बना दी है ताकि वाहनों की लोकेशन का पता लगाया जा सके। हमने बसों में सतर्कता बनाए रखने के लिए डी.टी.सी. बसों में 4,000 मार्शल भी तैनात किए हैं।

78. सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की समग्र सुरक्षा के लिए हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे और निगरानी प्रणाली लगाने का प्रस्ताव करते हैं। इसके अंतर्गत प्रारंभिक बजटीय आबंटन के रूप में वर्ष 2016–17 के दौरान 200 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है।

79. दिल्ली पुलिस और गैर–सरकारी संगठनों सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर 421 मार्गों पर कुल 42,000 अंधेरे स्थलों की पहचान की गई है। इन स्थलों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने का काम 2016–17 में पूरा किया जाएगा। इन चुने हुए स्थलों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के लिए 2016–17 के बजट में 114 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

80. महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर सिविल डिफेंस वालंटियर्स का मोहल्ला रक्षक दल बनाया गया है। इस प्रयास को स्थानीय नागरिकों और दिल्ली पुलिस द्वारा काफी सराहा गया है। इन सकारात्मक परिणामों को देखते हुए वर्ष 2016–17 में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मोहल्ला रक्षक दलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। मैं दिल्ली के सभी मोहल्लों में मोहल्ला रक्षक दल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

81. द्वारका में कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए 50 महिलाओं की क्षमता का छात्रावास 2016–17 में चालू हो जाएगा। 200 कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए दिलशाद गार्डन, पीतम पुरा और वसंत गांव में 3 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण कार्य वर्ष 2016–17 में शुरु किया जाएगा।

82. मैं, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 2016–17 में 1068 करोड़ रुपये का योजना बजट प्रस्ताव करता हूं।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

83. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के ऐसे कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता देने के लिए वचनबद्ध है, जिनके पास अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आय के स्रोत नहीं है या कम है। सरकार करीब 6 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ और निःसहाय महिलाओं के लिए वर्ष 2016–17 में 975 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव करती है।

84. वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार लाभार्थियों की जांच का एक व्यापक अभियान चला रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे और दोहरी सहायता लेने वाले या फर्जी लाभार्थियों का पता चल सके।

85. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि सरकार विभिन्न स्थानों पर नए वृद्धावस्था आश्रम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं प्रसन्नतापूर्वक यह बताना चाहूंगा कि इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया सभी पांचों स्थानों अर्थात् कांतिनगर, चितरंजनपार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार और छतरपुर में शुरू हो गई है। कांतिनगर में वृद्धावस्था आश्रम का निर्माण कार्य दिसंबर, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

86. इसके अतिरिक्त गीता कालोनी, जनकपुरी, सरिता विहार और वसंतकुंज में चार वृद्धावस्था आश्रमों और मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए उस्मानपुर में पुरुषों और दल्लूपुरा में महिलाओं के लिए दो गृहों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

87. रूज़वेल्ट ने कहा है "हमारी प्रगति की परीक्षा इस बात में नहीं है कि उन लोगों को और प्रदान किया जाए, जिनके पास पहले से प्रचुर मात्रा में है, बल्कि इस बात में है कि जिनके पास बहुत कम है उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया जाए"।

88. सरकार युवाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, और अल्प संख्यकों से सम्बद्ध युवाओं को प्रशिक्षण के जरिए बेहतर शिक्षा और कौशल प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे स्टेशनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, स्कॉलरशिप, प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की अदायगी आदि लागू किए जा रहे हैं। इन सभी कल्याणकारी योजनाओ और अनुसूचित जाति बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए 398 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

89. मैं 2016–17 में सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए 1381 करोड़ रूपये के योजना बजट का प्रस्ताव करता हूँ।

पानी और सीवर

90. अध्यक्ष जी, पीने का साफ पानी हर इंसान को चाहिए। वह राजा हो या रंक। और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराए। हमने हर घर को 20 किलोलीटर पानी निःशुल्क उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक फैसला किया था। इसके पीछे लक्ष्य सिर्फ समाज के निचले तबके को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि नागरिकों को पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। निर्धन और निम्न मध्य वर्ग से जुड़े करीब 10 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचा है।

91. अध्यक्ष जी, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 68 वर्ष बाद भी देश में हम लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। देश की बात तो छोड़िये राजधानी दिल्ली में ही एक बड़ी संख्या पीने के पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर है।

हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि दिल्ली की सभी अधीकृत, अनधिकृत कॉलोनियों में पीने का साफ पानी दिसम्बर 2017 तक पाईप लाइन के जरिये उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसमें से वर्ष 2016–17 में 300 नई अनधिकृत कालोनियों में पाइप लाईन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। मैं इस प्रयोजन के लिए 676 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। हमारा मकसद है दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाना और टैंकर माफिया का सफाया करना।

92. हमारी सरकार ने बीते एक साल में घर–घर तक पानी पहुचाने की दिशा में दिन–रात एक करके काम किया है। एक साल के दौरान हमने 217 कालोनियों को पाइप लाईन के जरिये पानी के नेटवर्क से जोड़ा है। जिनमें 167 किलोमीटर नई पाइप लाईन बिछाई गई और 19 किलोमीटर मौजूदा पाइप लाईन को बदला गया। दिल्ली की पिछली सरकारों की तुलना में यह बड़ी उपलब्धि है।

93. अध्यक्ष जी, हमने अनधिकृत कालोनियों में पानी की सुविधा का विकास शुल्क 440 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटा कर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। एक गरीब आदमी के लिए यह एक बड़ी राहत थी और विकास शुल्क कम करते ही 1,30,000 उपभोक्ताओं ने पानी का नया कनेक्शन ले लिया। इस योजना के प्रति भारी उत्साह को देखते हुए हमने इसे 18 जुलाई, 2016 तक बढ़ा दिया है।

94. अध्यक्ष जी, दिल्ली जल बोर्ड से लोगों की एक बड़ी शिकायत थी – पानी के विवादित बकाया बिल। खराब मीटर या मीटर रीडर की कारस्तानी के चलते दिल्ली के लाखों परिवारों पर 40–50 हजार से लेकर कई–कई लाख रूपये के बिल बकाया दिखाये जा रहे थे। मीटर रीडर और जल बोर्ड के कर्मचारी हमेशा ऐसे लोगों को परेशान करते थे। सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'ई' 'एफ' 'जी' और 'एच' श्रेणी की कालोनियों से संबंधित सभी उपभोक्ताओं के बिलों की शत प्रतिशत, 'डी' श्रेणी की कालोनियों के उपभोक्ताओं की 75 प्रतिशत, 'सी' श्रेणी के उपभोक्ताओं की 50 प्रतिशत तथा 'ए' और 'बी' श्रेणी की कालोनियों के उपभोक्ताओं की 25 प्रतिशत बकाया बिल राशि माफ करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही

लेट पेमैंट चार्ज पूरी तरह माफ कर दिया गया है। बिल पूरी तरह माफ किए जाने से निर्धन बस्तियों में रहने वाले लोग लंबे समय से विवादित वित्तीय बोझ समाप्त होने से खुश हैं, जबकि समृद्ध क्षेत्र के लोगों ने भी बकाया राशि में कमी को देखते हुए बिल जमा कराने में उत्सुकता दिखाई है। राजस्व वसूल करने वाली मशीनरी भी खुश है, क्योंकि उसे एक तरह से बट्टे खाते पड़ी राशि में से 20.27 करोड़ रूपये की वसूली करने में कामयाबी मिली।

95. 20 किलो लीटर तक मुफ्त पानी देने, पुराने बकाया बिल माफ करने जैसी योजनाओ का बड़ा लाभ दिल्ली जल बोर्ड को यह भी मिला है कि लोग आगे बढ़कर घरों में मीटर कनेक्शन लगवा रहे हैं। आज इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए घर में पानी का नया मीटर लगवाने वाले लोगों की लंबी कतारें लगती हैं। इसके विपरीत मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओ को तैयार करने के पिछली सरकारों के प्रयास व्यर्थ जाते थे।

96. अध्यक्ष जी, अपने कामकाज के एक वर्ष के भीतर, हमने द्वारका, बवाना और ओखला में 3 प्रमुख वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जोकि पहले बंद थे, को पुनः चालू करते हुए पेयजल की उपलब्धता में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है।

97. दिल्ली में अनियोजित विकास के कारण अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें पर्याप्त सीवेज डिस्पोजल सिस्टम स्थापित नहीं किया जा सका है। हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि दिल्ली जल बोर्ड समूची दिल्ली को सीवर प्रणाली प्रदान करने के लिए 2036 तक इंतजार नहीं करेगा, जैसा कि सीवरेज मास्टर प्लान में निर्धारित है। हमारा यह लक्ष्य है कि 8 से 10 वर्ष की अवधि में हम दिल्ली की सभी कॉलोनियों में सीवर बिछा सकें।

98. हाल ही में मुनाक नहर को क्षतिग्रस्त किए जाने से दिल्ली को पहली बार जल संकट का सामना करना पड़ा। परन्तु, दिल्ली जल बोर्ड ने जिस तरह निरन्तर शिकायत निवारण, जल प्रबंधन, टैंकर वितरण, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और

परियोजना प्रबंधन के उपायों के जरिए तेजी से कार्रवाई की, उससे संकट के प्रसार पर सुनिश्चित रोक लगायी जा सकी। मैं इस प्रयास के लिए दिल्ली जल बोर्ड की सराहना करता हूं। परन्तु, दिल्ली सरकार को यह अहसास हुआ कि वर्तमान में हमारा जल भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। अतः दिल्ली जल बोर्ड वर्षा जल संग्रह की व्यापक योजना तैयार करेगा, जल निकायों के जीर्णोद्धार की नीति अपनाएगा और ग्रीष्मकालीन कार्य–योजना तैयार करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।

99. मैं जलापूर्ति और सीवेज के लिए 1976 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कुल योजना परिव्यय का 9.6 प्रतिशत है।

बिजली

100. विद्युत क्षेत्र में हमारा लक्ष्य आम आदमी के लिए सस्ती और निरंतर बिजली आपूर्ति करना है। सरकार ने दरें कम रखने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 2015–16 में विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी और नियमित समीक्षा की बदौलत, हम औसत लोड शेडिंग को 0.15 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रख सके, जो अब तक का सबसे कम है। हमने अपना वायदा पूरा किया है और 400 यूनिट तक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं, अर्थात् कुल घरेलू उपभोक्ताओं के करीब 90 प्रतिशत परिवारों के बिजली के बिल 50 प्रतिशत कम कर दिए हैं। पहली बार, इस नीति का विस्तर एनडीएमसी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं तक किया गया है। मैं दिल्लीवासियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए, वर्ष 2016–17 के लिए 1,600 करोड़ रूपये की सब्सीडी का प्रस्ताव करता हूँ।

अनधिकृत कालोनियों का विकास

101. अनधिकृत कालोनियों में समयबद्ध तरीके से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों में सड़क एवं नालियां बनाने का काम डीएसआईआईडीसी को सौंपा गया है। अभी तक विकास कार्य केवल 895 अनधिकृत कालोनियों तक सीमित रहते थे। लेकिन अब सरकार ने नयी नीति के तहत निर्णय लिया है कि अगले वित्त वर्ष में दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों में सड़क और नालियों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए डीएसआईआईडीसी को 300 करोड़ रूपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है। इससे अधिक जितनी भी राशि की आवश्यकता डीएसआईआईडीसी को होगी वह अपने फंड से अथवा लोन लेकर इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। बाद में इसका भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त अनधिकृत कालोनियों में अन्य एजेंसियों द्वारा पहले से जारी कार्यों को पूरा करने के लिए 2016–17 में 190 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए हैं।

102. सरकार इन कालोनियों को नियमित किए जाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने इन नियमों का अनुमोदन कर दिया है, और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अधिसूचित करे ताकि ऐसी सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जा सके, जिनमें 01.01.2015 को 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका था।

झुग्गी–बस्तियों का विकास

103. दिल्ली में 675 झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए 3 लाख मकानों की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने "दिल्ली स्लम और झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति" तैयार की है, इसके तहत झुग्गी के बदले वैकल्पिक आवास पाने की पात्रता की नई कट–आफ डेट 4 जून, 2009 से बदल कर 1 जनवरी, 2015 करने का प्रस्ताव है। दिल्ली को 'स्लम मुक्त' क्षेत्र बनाने के लिए हमारी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वासियों के स्थानीय पुनर्वास का

कार्यक्रम (**जहां झुग्गी, वहां मकान**) शुरू किया है। पहले चरण में हमने प्रायोगिक आधार पर तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 20 झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के स्थानीय पुनर्वास की योजना बनाई है। इसके बाद हम इस मॉडल का अनुकरण दिल्ली के अन्य भागों में भी करेंगे। इस प्रयोजन के लिए 2016–17 के बजट में डीयूएसआईबी के लिए सीड मनी के रूप में 100 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

104. झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान करने के लिए नए शौचालय के निर्माण और मौजूदा जनसुविधा परिसरों के जीर्णोद्धार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया। अभी तक 93 शौचालय ब्लाकों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जिनमें 30 नए शौचालय ब्लाक हैं और 63 शौचालय ब्लाक ऐसे हैं जिनका जीर्णोद्धार किया गया है। इससे कुल शौचालय सीटों की संख्या में 4,500 से अधिक का इजाफा हुआ। हमारी सरकार ने 2016–17 में सभी झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में जन–सुविधा परिसरों के रूप में स्वच्छ शौचालय प्रदान करने का निर्णय किया है। मैं इसके लिए 100 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

105. मैं, आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए 2,466 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कुल योजना परिव्यय का 12 प्रतिशत है।

कला–संस्कृति

106. अध्यक्ष जी, कला–संस्कृति को दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाने की ओर कभी किसी राजनीतिक दल ने व्यापक ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार कला और सांस्कृतिक महोत्सवों को बड़े–बड़े सभागारों से निकालकर गली मोहल्लों तक ले जा रही है।

107. साहित्य कला परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ दर्जनों सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया; दिल्ली अभिलेखागार ने अभिलेखीय रिकार्डों

के डिजिटीकरण और माइक्रोफिल्मिंग की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया और पुरातत्व विभाग ने दिल्ली में 18 स्मारकों को संरक्षित किया तथा अग्रणी सड़कों पर स्थित 143 स्मारकों के संरक्षण की योजना बनाई।

108. आगामी वर्ष में, साहित्य कला परिषद शिक्षा विभाग के साथ मिल कर स्कूलों में प्रतिभा की खोज के लिए व्यापक अभियान चलाएगी ताकि रंगमंच, संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को स्कूली बच्चों में प्रोत्साहित किया जा सके और शहर में छिपी अद्‌भुत प्रतिभाओं को सामने लाया जा सके।

109. मैं कला, संस्कृति और भाषा के प्रोत्साहन के लिए 2016–17 में 54 करोड रूपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

पर्यटन और उत्सव

110. भारत की राजनीतिक राजधानी और ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद दिल्ली की संस्कृति की व्यापक अनदेखी हुई है और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किए जाने के उपायों पर नितांत अभाव रहा है। डीटीटीडीसी केवल पुल निर्माता और शराब विक्रेता संगठन बन कर रह गया। दिल्ली पर्यटन विभाग ने यथास्थिति बदलने और यह सुनिश्चित करने का अभियान शुरू किया है कि दिल्ली को विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल बने और कला, संस्कृति, संगीत, रंगमंच, फिल्म और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में देश का नेतृत्व करे।

111. कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और गतिविधियां दिल्ली से बाहर गुड़गांव और नोएडा में आयोजित की जाने लगीं थीं और दिल्ली परंपरागत सरकारी कार्यक्रमों का आयोजक बन कर रह गई थी, जो अधिकतर लुटियन दिल्ली में सीमित रहते थे, और छोटे थिएटरों में आयोजित किए जाते थे, जिनमें सीमित संख्या में लोग हिस्सा ले पाते थे। इसके अतिरिक्त आयोजनों के लिए अपेक्षित लाइसेंसो और मंजूरियों की संख्या ने इवेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोक दिया था। विभिन्न स्थलों पर

भ्रष्टाचार की वजह से भी दिल्ली में बड़े कार्यक्रमो का आयोजन लगभग बंद हो गया था।

112. सरकार ने दिल्ली में कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली शुरू की है, जिससे संबंधित प्रक्रिया इतनी सरल बन गई है कि लालफीताशाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं रहा है। इसके चलते हम आस्ट्रेलिया वर्ल्ड आर्केस्ट्रा में ए.आर. रहमान, जूबीन मेहता के मेगा शो, आईजीएनसीए, डिज्नीज़ ब्यूटी और बीस्ट आदि में कोअलिशन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज फेस्टिवल, पूर्वोत्तर उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम हैं। आने वाले वर्ष में सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली को जारी रखते हुए हम रेस्त्रां और Hospitality उद्योग के लिए भी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रस्ताव करते हैं।

113. धर्म, भाषा, क्षेत्र और व्यवसायों की विविधता के साथ दिल्ली भारत के बहु सांस्कृतिक और मिश्रित ताने बाने को प्रस्तुत करती है। हम दिल्ली फेस्टिवल नाम से एक विश्वस्तरीय उत्सव की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। यह ऐसा उत्सव होगा जो दिल्ली के लोगों की भावनाओं का सम्मान बढ़ाएगा और नागरिकों में गौरव जगाएगा। यह उत्सव हमारी शॉपिंग, संस्कृति, भोजन, संगीत, भाषाओं, रंगमंच और फिल्मों को प्रसिद्धि भी प्रदान करेगा।

114. हमारी सरकार "ब्रैंड दिल्ली" नाम का एक नया अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। हम वेबसाइटों, एप्स, मैप्स, सोशल मीडिया और माइक्रो–साइट्स के जरिए पर्यटक स्थल के रूप में दिल्ली की ऑनलाइन मौजूदगी को दर्ज कराऐंगे। मैं 2016–17 में दिल्ली ब्रैंड और दिल्ली फेस्टिवल के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

115. 2016–17 में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से कुतुब मीनार तक एक स्काईवॉक–वे बनाने का प्रस्ताव है जो अपनी तरह का अनूठा मार्ग होगा। उक्त वॉक–वे मेहरौली पुरातत्व परिसर के ऊपर से जाएगा।

116. मैं 2016–17 में पर्यटन ढांचे के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

117. दिल्ली भारत की राजधानी है और देश का सांस्कृतिक हृदय है, फिर भी इस गतिशील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश ऐसा नहीं है, जो प्रवेशकर्ता को कुछ अद्‌भुत या वैभवशाली महसूस कराए। दिल्ली पर्यटन विभाग को शहर की सीमाओं का जीर्णोद्धार करने के लिए अपेक्षित अनुमतियां मिल गई हैं और वह सड़क मार्ग से गाजीपुर तथा धौलाकुआं जैसे दिल्ली प्रवेश बिंदुओं का सौंदर्यकरण करेगा।

118. मैं अब अपने भाषण का भाग 'ख' प्रस्तुत करता हूं।

भाग–ख

119. माननीय अध्यक्ष जी, अपने भाषण के भाग–क में मैंने सरकारी की नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला है, और मैं एक बार फिर पूर्ण दृढ़ता के साथ कहता हूं कि यह सरकार दिल्ली के आम आदमी द्वारा और आम आदमी के लिए है। करों और शुल्कों के रूप में दिल्ली के लोगों से वसूल किया गया एक–एक रुपया अत्यन्त ध्यानपूर्वक और ईमानदारी तथा निष्ठा पूर्वक खर्च किया जाता है।

120. यह धारणा सही नहीं है कि केवल अमीर कर अदा करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के रूप में उपभोक्ता के नाते निर्धन और उपेक्षित व्यक्ति भी कर अदा करते हैं। अतः पहले वर्णित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें एक तरफ अधिक संसाधन जुटाने होंगे, वहीं दूसरी तरफ हम एक न्यायोचित, निष्पक्ष और स्थिर कर संरचना के प्रति संकल्पबद्ध हैं।

121. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पारदर्शी, ईमानदार और प्रभावकारी शासन की बदौलत समग्र राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस उपलब्धि का श्रेय उच्चतम स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त होने और उन स्तरों

पर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को जाता है, जहां नागरिकों का अंतर–संपर्क सरकार के साथ होता है। संवेदनशील पदों पर ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति, कम लागत पर ढांचागत परियोजनाओं को पूरा किए जाने और फिजूलखर्ची में कमी की भी इसमें अहम भूमिका रही है।

मूल्य सवंर्द्धित कर (वैट)

122. अध्यक्ष जी, कर राजस्व, वैट सरकार की प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा है, जिसका कुल वसूली में 65 प्रतिशत योगदान है और हमारी अधिकतर विकास गतिविधियां मुख्य रूप से वैट से प्राप्त कर राजस्व में वृद्धि और लचीलेपन पर निर्भर हैं। मेरे कराधान प्रस्ताव निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित हैं :

123. हमारी टैक्सेशन पॉलिसी का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है – दिल्ली के व्यापार के डिस्ट्रीबूटिव करेक्टर को बनाए रखना।

124. हमारी टैक्स पॉलिसी का दूसरा सिद्धांत है – वर्तमान व्यवस्था को सरल बनाना और **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'** को हर तरफ से प्रोत्साहन देना।

125. तीसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में, मैं कहना चाहता हूँ – दिल्ली में विभिन्न आईटम्स के अलग–अलग लिस्टस में मल्टीपल एंट्रीस से पैदा हुए भ्रम को दूर करना। आईटम्स की मल्टीपल एंट्रीस से गड़बड़ी के अवसर भी पैदा होते हैं और व्यापारियों को तंग करने के अवसर भी पैदा होते हैं।

126. हमारी चौथी कोशिश है – टैक्स की दरें पड़ोसी राज्यों की दरों से समान हों। मिठाइयां–नमकीन, घड़ियां, रेडीमेड गारमेंट्स जैसी कई ऐसी वस्तुएं हैं, जिन पर पड़ोसी राज्यों में कर की दर कम है, जिससे विषम स्थिति पैदा होती है। हमने वैट ढांचे में इस तरह के असंतुलन दूर करने के प्रयास किए हैं।

127. अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है, कि हम वॉलेन्टरी कम्पलायंस को प्रोत्साहित करते हैं।

128. उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं वैट की दरों में संशोधनों का प्रस्ताव करता हूं, जिन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

- वैट दरों में कमी।
- कर की दरों को तर्कसंगत बनाना।

वैट की दरों में कमी

129. हमारी सरकार ऑटोमोबाइल्स के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। बैटरी से संचालित यातायात के साधनों जैसे – **ई–रिक्शा, बैटरी प्रचालित वाहनों और हाई–ब्रीड ऑटोमोबाइल्स (अर्थात् अन्य ईंधन विकल्प के साथ बैटरी संचालित)** पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

130. **मिठाइयो और नमकीनों** पर वर्तमान में 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगता है। भौगोलिक कर विवाचन से बचने के लिए, मैं मिठाइयों और नमकीनों पर वैट की दर घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

131. वर्तमान में 5,000/– रुपये मूल्य तक के **रेडीमेड गारमेंट्स** पर 5 प्रतिशत और 5000/– रुपये से अधिक मूल्य के रेडीमेड गारमेंट्स पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। पड़ोसी राज्यों (उत्तर प्रदेश और हरियाणा) में सभी रेडीमेड गारमेंट्स पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। मैं इस विसंगति को दूर करने के लिए सभी रेडीमेड गारमेंट्स पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

132. दिल्ली में **मार्बल** पर वर्तमान में, अनिर्दिष्ट वस्तु होने के नाते, 12.5 प्रतिशत कर लगता है। मार्बल ट्रेड आसोसिएशन आफ दिल्ली, ने लोगों को केवल दिल्ली के व्यापारियों से मार्बल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए, मार्बल पर कर में कमी लाने का अनुरोध किया था। मैं समझता हूं कि मार्बल पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करना राजस्व के हित में होगा और मैं तदनुरूप प्रस्ताव करता हूं।

कर की दरों को तर्कसंगत बनाना

133. दिल्ली में **घड़ियों** पर अलग–अलग दरों से कर लगाया जाता है, जो 5000/– रुपये मूल्य तक की घड़ियों पर 12.5 प्रतिशत और 5000/– रुपये से ऊपर की घड़ियों पर 20 प्रतिशत की दर से लगता है, जबकि पड़ोसी राज्यों में सभी घड़ियों पर एक समान दर से 12.5 प्रतिशत कर लगाया जाता है। मैं सभी प्रकार की घड़ियों पर 12.5 प्रतिशत की एकसमान दर से वैट लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

134. **टेक्सटाइल और फैब्रिक** वर्तमान में कर दर अनुसूचियों में अनेक एंट्रियों के अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं –जिनमें से कुछ कर–मुक्त सूची में आते हैं, जबकि अन्य 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। मैं इस प्रणाली को सरल बनाने के लिए खादी और हैंडलूम वस्त्रों को छोड़ कर सभी प्रकार के टैक्सटाइल और फैब्रिक (साड़ियों सहित) पर 5 प्रतिशत की समान दर से वैट लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

135. **प्लास्टिक वेस्ट** अभी तक कर मुक्त रहा है जबकि कच्चे प्लास्टिक पदार्थ जैसे प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक पाउडर और प्लास्टिक की बड़ी खेपों (मास्टर बैचेज़) पर 5 प्रतिशत कर लगाया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट को चूंकि रिसाइकिल करके प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, अतः मैं प्लास्टिक वेस्ट पर भी 5 प्रतिशत की समान दर से वैट लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

136. वर्तमान में **इन्वटरर्स और यूपीएस** 12.5 प्रतिशत की सामान्य अनिर्दिष्ट दर से कर योग्य हैं। परंतु, कर योग्य वस्तुओं की अनुसूची–3 में यूपीएस यूनिट्स नाम से एक डुप्लीकेट एंट्री है, जिससे भ्रम पैदा होता है। मैं इस एंट्री को हटाने का प्रस्ताव करता हूं।

137. वर्तमान में 500/– रुपये से ऊपर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) वाले **फुटवियर** पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगता है। मैं फुटवियर पर वैट की दर को तर्कसंगत बनाने के लिए सभी प्रकार के फुटवियर पर 5 प्रतिशत की एकसमान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

138. वर्तमान में 300/– रुपये तक अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) वाले **स्कूल बैगों** पर 5 प्रतिशत और 300/– रुपये से अधिक एमआरपी वाले स्कूल बैगों पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। मैं स्कूल बैगों पर वैट की दर को तर्कसंगत बनाने के लिए उनके मूल्य पर विचार किए बिना सभी प्रकार के स्कूल बैगों पर 5 प्रतिशत की एकसमान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

139. **लौह और अलौह धातुओं** की वर्तमान एंट्री के अंतर्गत, अल्युमीनियम या मैटल शीटों का उल्लेख नहीं है और कुछ वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की उच्चतर दर से कर लगाया जाता है। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, मैं तत्संबधी एंट्री को निम्नांकित रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं –"लौह और अलौह धातु और उनकी शीटें, परतें, निष्कर्षण सहित उनके मिश्रण। अलौह धातुओं में अल्युमीनियम, तांबा, जस्ता आदि शामिल हैं"।

140. अध्यक्ष जी, **तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद** पर वर्तमान मे 20 प्रतिशत की दर से कर लगता हैं। सम्बद्ध एंट्री का विवरण इस प्रकार है :–

"Tobacco and Gutkha, unmanufactured tobacco, bidis and tobacco used in manufacture of bidis and hooka tobacco".

इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए मैं इस एंट्री को निम्नांकित रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं :–

"Un-manufactured tobacco, tobacco and tobacco products in all forms such as cigarettes (irrespective of form and length), chewing tobacco, gutkha, cigars, hookah tobacco, khaini, zarda, surti, bidis etc."

141. वैट की दरों से संबंधित सुधारों के अतिरिक्त, सरकार ने कर प्रबंधन में जनता की भागीदारी पर अधिक बल दिया है। इसके लिए बिल बनाओ, ईनाम पाओ नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में उपभोक्ता, कोई सामान खरीदते समय खुदरा बिल/इन्वायस का स्नैप शॅाट मोबाइल अप्लीकेशन के जरिए विभाग को भेज सकते हैं। इस नए कार्यक्रम ने जनता और वैट विभाग के बीच एक बेजोड़ भागीदारी को बढ़ावा दिया है। यह जांच अभी तक मुख्य रूप से इंसपेक्टर्स के फील्ड में दौरे पर निर्भर थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अवार्ड और पुरस्कार राशि के लिए 1 प्रतिशत प्रविष्टियों का चयन किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं की भागीदारी प्रोत्साहित की जाती है। कार्यक्रम की बढ़ती सफलता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि फरवरी, 2016 के दौरान 8,000 एंट्रियां प्राप्त हुईं, जबकि कार्यक्रम की शुरूआत के महीने, जनवरी 2016 में 4,000 एंट्रियां प्राप्त हुई थीं।

142. सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत उन बाजार और व्यापार संगठनों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया जाता है, जो वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों से ऊपर राजस्व में योगदान करते हैं। ऐसे संगठन वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक और ऊपर अर्जित राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्व में सर्वाधिक योगदान करने वाले 10 शीर्ष बाजार संगठनों को भी, प्रत्येक को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

पुरस्कार राशि का इस्तेमाल बाजार के समग्र सुधार और जनसुविधाओं के रख–रखाव, सौंदर्यकरण, मरम्मत कार्यों आदि के लिए किया जाएगा।

143. अध्यक्ष जी, ऊपर दिए गए ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार अतीत में कमान, नियंत्रण और बाजार में घुसपैठ करने वाली परंपरागत सरकारों से भिन्न है, जो समर्थक और सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करती है।

उत्पाद शुल्क, स्टैम्प शुल्क और विलासिता कर

144. अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में शराब के व्यापार को सुचारू बनाने और भ्रष्टाचार दूर करने की बात कही थी। आज मैं प्रसन्नता के साथ सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों के अनुकूल परिणाम आने लगे हैं।

145. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने पिछले वर्ष शराब पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की थी। परंतु, आबकारी राजस्व में लीकेज रोकने के लिए कमियां दूर करने के उपाय किए थे। हमने उत्पाद शुल्क लगाए जाने का बिंदु ट्रांसपोर्ट परमिट लेवल से आयात परमिट लेवल पर स्थानांतरित किया था। इसके कारण और सरकार द्वारा किए गए अन्य सुधारों की बदौलत आबकारी राजस्व वसूली में 31 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और यह 2014–15 मे 3,187 करोड़ रुपये से बढ़ कर इस वर्ष करीब 4,200 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस प्रकार इंस्पैक्टर राज पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। आने वाले समय में ये मौजूदा सुधार न केवल जारी रखे जाएंगे, बल्कि कुछ और सुधार भी शुरु किए जाने की संभावना है।

146. विलासिता कर से राजस्व वसूली में 36.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष विलासिता कर से 322 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि इस वर्ष 440 करोड़ रुपये की वसूली होने का अनुमान है।

147. सरलीकृत कर व्यवस्था की दिशा में एक और कदम रखते हुए, मैं विलासिता कर की सीमारेखा मौजूदा 750 रुपये से बढ़ा कर 1500 रुपये करने की घोषणा करता हूं। इससे नागरिकों और पर्यटकों पर कर का बोझ कम होगा और छोटे होटलों को व्यापार करने में आसानी होगी।

148. आज की स्थिति के अनुसार सभी होटलों का मूल्यांकन अनिवार्य है। सरकार ने विलासिता कर के मामले में स्व–घोषणा पद्धति शुरू करने का निर्णय किया है। मूल्यांकन आकस्मिक आधार पर किया जाएगा।

149. मनोरंजन कर से राजस्व वसूली में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई। मनोरंजन कर से पिछले वर्ष 148 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि इस वर्ष 237 करोड़ रुपये वसूल किए जाने का अनुमान है।

150. अध्यक्ष जी, सरकार इस बात के प्रति अत्यंत सजग है कि कर/शुल्कों की दरें आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अचल संपत्ति के क्षेत्र में मंदी को देखते हुए, हमारी सरकार ने (पिछली नीतियों से भिन्न) शहरी क्षेत्रों में सर्कल दरें स्थिर रखीं और उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है 31 मार्च 2015 तक स्टैम्प शुल्क वसूली 2,779 करोड़ रुपये की हुई। चालू वर्ष में 22.03.2016 तक स्टैम्प शुल्क वसूली 3,359 करोड़ रुपये की रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए विभिन्न नए उपाय प्रस्तावित किए जा रहे हैं ताकि स्टैम्प शुल्क वसूली में भारी वृद्धि की जा सके।

151. दिल्ली के लिए एक अलग स्टैम्प एक्ट तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रावधानों को सरल करना, निरंकुश अधिकारों में कमी लाना और साथ ही राजस्व में वृद्धि करना है। एक नई पहल शेयर और डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियों के लिए स्टैम्प शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के रूप में की जा रही है। अधिक से अधिक लेनदेन को पंजीकरण और स्टैम्प शुल्क के दायरे में लाने के प्रयास किए

जा रहे हैं। पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 में संशोधन प्रस्तावित हैं, ताकि कई नए संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जा सके।

152. हमारी सरकार पंजीकृत दस्तावेज के लिए जल्द ही ऑनलाइन सर्च सुविधा शुरू करने पर विचार कर रही है। 1985 के बाद से सभी धरोहर आंकड़ों को स्कैन, डिजिटीकृत किया जाएगा और आम लोगों को आसानी से सर्च के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

''''''

''मुझे सबको संतुष्ट करना अच्छा लगता है, बशर्ते ऐसा कर सकना मेरे लिए संभव होता; परन्तु, सभी को संतुष्ट करने के प्रयास में, शायद मैं किसी को भी संतुष्ट न कर पाऊं। इसलिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहिए और दुनिया को अपना निर्णय स्वयं करने के लिए छोड़ देना चाहिए, अनुकूल या प्रतिकूल''

— महात्मा गांधी